उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार में प्रसारित

सम्पादक : अखिल कुमार 'कृपाशंकर'

RNI NO. UPHIN/3844/2001

राष्ट्रीय मानवाधिकार

मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीड़न एवं बाल श्रम पर केन्द्रित हिन्दी साप्ताहिक समाचारपत्र

डाक पंजि. संख्या मेरठ-147-2015-2017

सेवा में,

Website:-www.rashtriyamanavadhikar.com

Email:-rashtriyamanavadhikar@gmail.com

वर्ष: 17, अंक: 29 | मेरठ, सोमवार, 13 नवम्बर 2017 से 19 नवम्बर 2017 | मुल्य एक रूपया

हम सरकार नहीं साढ़े सात करोड़ लोगों का परिवार चलाते हैं- सीएम

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता हमारा अपना परिवार है। हम सरकार नहीं परिवारभाव से सेवा कार्य में जुटे हुए है और इसी भाव से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे है। सरकार की योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचाने में मुख्यमंत्रीजनकल्याण प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बात मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में बुधवार को मुख्यमंत्री जनकल्याण प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि साढ़े सात करोड़ जनता रूपी परिवार के सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमें समर्पण के साथ जुटना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकोष्ठ का मंडल स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकोष्ठ में शासन के कमोवेश सभी विभागों की जनकल्याण योजनाएं समाहित है इसलिए इसकी कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के लिए प्रकोष्ठ और पार्टी पूरी गंभीरता के साथ जुटी है। सीएम ने कहा कि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता योजनाओं का प्रचार प्रसार

करें।

हेल्पलाइन का लें सहारा

सीएम ने कहा कि योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो इसके लिए योजनाओं का अध्ययन करें।

उन्होंने योजनाओं के प्रस्तुतीकरण को लेकर प्रकोष्ठ के एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26 लाख 30 हजार लाड़ली लक्ष्मी नामित हो चुकी है और इन्हें निश्चित रूप से लाभ दिया जा रहा है। इनके परिवार हमारे हितग्राही है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन हमारे लिए वोट नहीं भगवान है।

उनकी मदद और चिंता करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार ने वृद्धजन हेल्पलाइन बनाने का निश्चय किया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो दागी MP, MLA के खिलाफ सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि दागी नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना बताए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, दागी नेताओं के केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। स्पेशल कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेगी। इसमें कितना वक्त और फंड लगेगा यह 6 हफ्तों में बताएं।

–सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा आप बताएं कि खर्च कितना होगा फिर हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति और इंफ्रा स्ट्रक्चर कैसे होगी।

–पहले केंद्र सरकार ने कहा हम स्पेशल कोर्ट के लिए तैयार हैं पर ये राज्यों का मामला है, तब कोर्ट ने कहा कि आप सेंट्रल स्कीम के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड बताएं कि कितना लगेगा।

–कोर्ट में पेटिशनर के तरफ से बताया गया कि चुनाव आयोग में उम्मीदवारों के द्वारा दिए गए हलफनामे के मुताबिक 2014 में 1581 MP और MLA के खिलाफ केस थे।

–कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकार बताये कि इन मामलों में अब तक क्या हुआ।

–अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार हिन्दी साप्ताहिक समाचार–पत्र में कुछ समाचार इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि उन समाचारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग उन पर संज्ञान लें।

भ्रष्टाचार पर नर्म हुई मोदी सरकार ने नहीं दी यूपी कैडर के आईएएस सदाकांत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त रुख रखने के दावा करती रही है स पर लखनऊ के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के प्रति लचीला रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया है स यह फायरब्रांड समाजसेवी लखनऊ निवासी संजय शर्मा हैं जिनके द्वारा दायर की गई एक आरटीआई के जबाब में भारत सरकार के कार्मिक ,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अवर सचिव और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी राज किशन बत्स ने संजय को बताया है कि मोदी सरकार ने यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी सदा कांत शुक्ल द्वारा साल 2011 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर रहते किये गए 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज कराई गई एफ्आईआर पर सदा कांत शुक्ल के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है स देश के अग्रणी आरटीआई कंसलटेंट संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने यह आरटीआई बीते जुलाई की 25 तारीख को दायर की थी जिसके जबाब में उन्हें बताया गया है कि बीते सितम्बर की 18 तारीख को भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने सदा कांत शुक्ला के खिलाफमुकदमा चलाने के लिए मंजूरी के प्रस्ताव को इंकार कर दिया है स

संजय ने बताया कि उन्होंने सदा कांत शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में जारी आदेश, नोटशीट्स और टिप्पणियों की भी मांग की थी पर सीपीआईओ बत्स ने कहा है कि यह सूचना देने पर अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी और आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) के तहत ये सूचना देने से इंकार कर दिया है स

संजय बताते हैं कि सदाकांत पर साल 2011 में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत और चीन की संवेदनशील सीमा पर सड़क निर्माण में जासूसी करने का आरोप लगने के बाद सीबीआई ने सदाकांत के दिल्ली आवास पर छापा मारकर तलाशी ली थी और एफ्आईआर दर्ज कर साल 2012 में सदाकांत के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति माँगी थी । बकौल संजय केंद्र की तत्कालीन सरकार ने सदाकांत को पद से हटा कर सीबीआई को भी उनसे पूछताछ की इजाजत देते हुए सदाकांत को प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने से पहले ही पैरेंट कैडर वापस भेज दिया था ।

5 साल बाद सदाकांत के भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियोजन स्वीकृति तक न देने के आधार पर संजय ने मोदी सरकार को भ्रष्टाचार विरोध पर कठघरे में खड़ा करते हुए सदाकांत के इस मामले को उच्च न्यायालय ले जाने की बात कही है स

आधार पर ममता को कड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'संसद पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं'

नई दिल्ली. आधार कार्ड को कल्याणकारी योजनाओं से लिंक किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार को फटकार मिली है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की खिंचाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी को एक व्यक्ति के तौर पर अपील दायर करनी चाहिए थी. संसद द्वारा पारित कानून पर एक राज्य सवाल खड़ा नहीं कर सकता है. कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने पूछा है कि संघीय व्यवस्था में एक राज्य कैसे संसद के जनादेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से कहा, 'हम समझते हैं कि यह विचारणीय मुद्दा है, लेकिन आप हमें समझाएं कि एक राज्य इसे कैसे चुनौती दे सकता है.' मोबाइल फोन नंबर को आधार से जोड़े जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है. बता दें कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम को ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. न्यायामूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की.

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संसद सदस्य कल्याण बनर्जी ने बताया था कि कि याचिका पहले ही दायर की गई थी और पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह 30 अक्तूबर को आएगी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें

कहा गया है कि आधार के बगैर समाज कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. गौरतलब है कि बुधवार को कोलकाता में एक बैठक में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आधार को मोबाइल फोन नंबर से जोड़े जाने का भी विरोध करते हुए कहा था, 'आधार नंबर को किसी के मोबाइल फोन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. मैं अपने आधार नंबर को अपने मोबाइल से नहीं जोडूंगी, मेरा कनेक्शन कट जाए तो भी नहीं.' हालांकि कल्याण बनर्जी ने बताया कि आधार-मोबाइल मुद्दा राज्य सरकार की याचिका का हिस्सा नहीं है. गौरतलब है कि कल्याण योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किए जाने के केंद्र के कदम और इसे मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते से जोड़े जाने की अधिसूचनाओं के खिलाफ कई याचिकाएं शीर्ष न्यायालय में लंबित हैं।

सम्पादकीय

नोटबंदी का असर चौतरफा मंदी से बढ़ी चुनौतियां

बीते साल आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह फैसला लिया था, जिसे सरकार से लेकर आमजन तक नोटबंदी की घोषणा के रूप में शायद हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने एक साल पहले पांच सौ और एक हजार रुपये के नोटों को रद्द करते समय तीन कारण गिनाए थे। पहला कारण था काले धन को समाप्त करना, दूसरा जाली नोटों की समस्या को हल करना और तीसरी बात थी 'आतंकवाद' के आर्थिक स्रोतों को बंद करना। इस फैसले का एक अरब से अधिक लोगों के आम जनजीवन पर ऐसा असर पड़ा कि इस भारतीय नोटबंदी को हाल के इतिहास में किसी भी देश के सबसे अधिक असर डालने वाले आर्थिक नीतिगत फैसले में शुमार किया जा रहा है। इरादे नेक गिनाए गए थे, लिहाजा मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर रिचर्ड थालर ने भारत सरकार के इस फैसले की मुक्तकंठ सराहना की थी। मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने नरेंद्र मोदी के नोबेल आइडिया को प्रो. थालर से मिली प्रशंसा को खूब प्रचारित भी किया, लेकिन इन्हीं प्रो. रिचर्ड थालर को जब पता चला कि मोदी सरकार ने दो हजार रुपये का नया नोट बाजार में उतार दिया है तो इस नोबेल अर्थशास्त्री ने अपना माथा पीट लिया और सोशल मीडिया पर इस कृत्य को भयंकर भूल करार देने में देर नहीं लगाई।

जब नोटबंदी के चलते बैंकिंग और नोटप्रवाह प्रणाली ध्वस्त हो गई और कानून व्यवस्था चरमराने लगी तो सरकार को सेना की मदद तक लेनी पड़ी और एक महीने बाद ही पीएम मोदी को दोबारा जनता के सामने आना पड़ा। इस बार उन्होंने दावा किया कि भारत को 'कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था' की ओर ले जाने के लिए नोटबंदी जरूरी थी। नोटबंदी पर मोदी ने अपने भाषणों में 'कैशलेस और डिजिटल' शब्द का जितनी बार इस्तेमाल किया, वो इन भाषणों में 'काला धन' शब्द से तीन गुना अधिक थे जबकि आठ नवंबर के अपने संबोधन में उन्होंने 'कैशलेस और डिजिटल' शब्द का नाम तक नहीं लिया था। नोटबंदी का असर आजतक महसूस किया जा रहा है और अर्थशास्त्रियों ने बीते साल के मुकाबले आज दिख रहे जीडीपी ग्राफके ढलान पर चिंता जताई है। इनमें पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा भी शुमार रहे। बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था के अलंबरदारों ने भी यह स्वीकारा कि नोटबंदी का आइडिया अच्छा भी रहा हो तो इस मायाजाल से निपटने के तौर तरीके चुस्त-दुरुस्त नहीं रहे। नोटों की किल्लत और डिजिटलाइजेशन की जटिलताओं ने जीएसटी लागू करने में हुई चूक और अव्यवस्था के साथ मिलकर माहौल ऐसा बिगाड़ा कि आर्थिक मंदी, औद्योगिक सुस्ती और नौकरियों के अवसर खोने से उपजी निराशा के रूप में देश के सामने नई चुनौतियों खड़ी कर दी हैं।

जब 32 की उम्र में लता मंगेशकर को दे दिया गया था धीमा जहर

पिता क्लासिकल सिंगर

भारत की स्वर सम्राज्ञी कही जाने वाली लता मंगेशकर आज विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी हैं। 28 सितम्बर 1929 को इंदौर में जन्मीं लता की गायन कला पैतृक देन है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर उस दौर के एक मशहूर क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। भाई बहनों में ये सबसे बडी थीं।

अभिनय की शुरुआत

जब वह मात्र 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने 1942 में अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद 1945 में मुंबई आने के बाद उन- होंने उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल गायन सीखा।

पतली आवाज छा गई

लता ने 1946 में हिंदी फिल्मों में पा लागूं कर जोरी... गीत गाकर करियर की शुरुआत की। हालांकि पहले तो इनकी पतली आवाज पर फिल्ममेकर थोड़ा पीछे हटे लेकिन बाद में दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा... गाए गीत की काफी तारीफ हुई। इसके बाद इनक गायन का सफर तेजी से चल पड़ा।

मारने की कोशिश

जब लता 1962 में 32 साल की थी तब एक दिन उनकी अचानक से तबियत बगड़ी। पेट दर्द और उल्टियों की वजह से बुरा हाल था। लता की हालत गंभीर थी। इस दौरान डॉक टर ने उन्हें उपचार देने के साथ ही बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा। इसके बाद उनका रसोइया बिना बताए भाग गया था।

मिल चुके ये सम्मान

लता मंगेशकर ने अब तक 36 से भी ज्यादा भाषाओं में करीब 30 हजार से अधिक गाने गाए हैं। लता मंगेशकर को अब तक कई बड़े पुरस- कार मिल चुके हैं। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न जैसे सम- मान प्राप्- त हुए हैं।

सड़क पर बेरीकेट्स व तम्बू लगाकर किया आवागमन ठप

नेशनल हाईवे की बदहाली को लेकर व्यापारी संघ ने किया प्रदर्शन

सीतापुर। नगर के मध्य से होकर गुजर रही नेशनल हाईवे 43 सड़क की बदहाली को लेकर नागरिकों ने नगर के कारगिल चौक के समीप सड़क पर बेरिकेट और तम्बु लगाकर आवागमन ठप कर दिया। सीतापुर के व्यापारी संघ द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में भारी संख्या में नागरिकों द्वारा बदहाल सड़क और सड़क से उठती धूल के विरोध में प्रदर्शन किया। विदित हो कि शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली एनएच 43 शहर के बाहर सोनतराई होते हुये बायपास सड़क बन रही है। इन दिनों जर्जर हो चुकी सड़क दुर्दशा का दंश झेल रही हैं। लोगों ने गुरूवार को चक्काजाम करते हुये सड़क पर ही तम्बु लगा आवागमन ठप्प करते हुये सड़क सुधार के नारे लगाने शुरू कर दिये थे। इस दौरान भारी संख्या में नागरिकों की भीड़ इकटठा हो गई थी।

नागरिकों द्वारा एक स्वर मे एनएच विभाग के खिलाफनारे लगाकर बदहाल सड़को की परेशानी से जल्द छुटकारा दिलाने की बातें कही जा रही थी। उनका कहना था कि बारिश का मौसम समाप्त होते ही यह निर्माण सामग्री पूरी सड़क पर बिखर गई और सड़क पर वाहन गुजरने के दौरान धूल अत्याधिक मात्रा में उडने लगती है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्काजाम के दौरान व्यापारी संघ अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, रमेश गुप्ता, सौरभ अग्रवाल सहित काफी संख्या में व्यापारी व नागरिकगण उपस्थित थे।

ये हैं वो खिलाड़ी जो इस साल बने मम्मी-पापा

सेरेना विलियम्स

अमेरिकन टेनिस सनसनी सेरेना विलियम्स ने हाल ही में एक फ्लोरिडा के सेंट मैरी मेडिकल सेंटर में एक बेटी को जन- म दिया है। जानकारी के मुताबकि 23 ग्रैंड स्लेम जीतने वाली सेरेना विलियम्स और उनका बेबी दोनों ही स्वस्थ्य हैं। इस दौरान सेरेना विलियम- स को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है।

रवींद्र जडेजा

इसी साल जून में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर क्रिकेटर रवींद्र जडेजा भी पि ता है। उनकी पत्नी रीवा ने भी राजकोट के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में क्यूट सी बेटी को जन्म दिया है। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की शादी बीते साल 17 अप्रैल 2016 को हुई थी

गौतम गंभीर

जून में ही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गौतम गंभीर भी पि ता बने हैं। उनके घर भी एक नन्ही परी आई है। गौतम गंभीर दूसरी बार पिता बने हैं। उन- होंने अपनी नन- हीं परी के लिए सोशल मीडिया पर लिखा था कि हमारे परिवार में एक परी आई है, उस परी ने हमारे जीवनों को रोशनी से भर दिया है।

फ्लाविया पेनेटा

इटली की टेनिस स्टार फ्लाविया पेनेटा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस साल मई में फ्लाविया पेनेटा ने एक बेबी ब वॉय को जन्म दिया है। इस दौरान उन- हें भी सोशल मीडिया पर ढेरों बधाइयां मिली। फ्लाविया पेनेटा ने अपने बेबी ब वॉय का नाम फेडरिको रखा है।

स्कूल की जर्जर इमारत, सड़क का गंदा पानी, बच्चों के बने 'दुश्मन जानी'

फरीदाबाद (अनिल राठी) जी हां! फरीदाबाद के गांव शाहपुर खुर्द के माध्यमिक स्कूल की इमारतें जर्जर हैं, और स्कूल जानें वाली सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में बच्चों की जान को खतरा बना ही रहता है, साथ ही बच्चे अपना जूता हाथ में लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल जाते हैं, वहीं स्कूल पहुंचते ही उनकी जान पर बनी रहती है, ऊपर से रास्ते में कीचड़ और गंदे पानी ने अलग परेशान किया हुआ है।

गांव शाहपुर खुर्द के सरकारी माध्यमिक स्कूल के सैकड़ों छात्र-छात्राएं इन दिनों जहां एक ओर जहां पढाई करने के लिए जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। वहीं स्कूल की जर्जर इमारतें बच्चों के दिमाग में दहशत पैदा कर रही हैं कि कहीं किसी दिन कोई हादसा न हो जाए। बात यहीं नहीं खत्म होती, दरअसल बच्चों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं हैं। स्कूल में रंग-रोगन की बात तो दूर कक्षाओं में लगे ब्लैकबोर्ड के प्लॉस्टर तक टूटे हुए हैं, दीवारें और छतों के बीच दरारें पड़ी हैं, साथ ही दीवारों और पिलरों में तो 2-2 इंच की दरारें आ गई हैं। लकड़ी के ब्लैकबोर्ड आधे खत्म नजर आते हैं। उक्त समस्याओं जैसी अन्य समस्याएं भी स्कूल में हैं। ऐसे में कौन अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा।

दूसरी तरफ, गांव में अगर बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलें तो रास्ते में दो-दो फुट तक गंदे पानी का भराव परेशान करता है। बच्चों को यही डर रहता है कि, कहीं वो फिसल कर गिर न जाएं या कोई कार वाला उस पानी से चीरता हुआ निकले और उनके कपड़े खराब हो जाए।

उक्त समस्याओं को लेकर जब स्कूल के प्रिसिंपल अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि, जर्जर इमारतों की शिकायत शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप में दी गई है, जिसे समय रहते ठीक करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, उनके यहां टीचरों की भी कमी है। ग्रामीणों ने बताया कि, उनके बच्चे आए दिन स्कूल जाते समय इस गंदे पानी में गिर जाते हैं जिसको लेकर कईबार सरपंच व प्रशासन से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन टालम-टाल में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।

इस बारे में गांव के सरपंच से इन्द्रराज से बात की गई तो उन्होंने ग्रामीणों पर आरोप जडने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि ग्रामीणों ने जोहड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये पानी रास्ते में भरा पड़ा है। साथ ही जब स्कूल के एक मात्र रास्ते पर भरे हुए गंदे पानी के बारे में खंड विकास एंव पचांयत अधिकारी पूजा शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके संज्ञान में ये बात आई है और जल्द ही इस गंदे पानी की निकासी का प्रबंध कर दिया जाएगा।

पोलोटैक्नीक के पीड़ित छात्रो को मिली जान से मारने की धमकी

जहांगीराबाद। नगर के भईपूर दोराहे पर बवे होस्टल में रहने वाले पॉलटेक्नीक के चार छात्रो केा कुछ अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी ओर कहा अगर तुमने फैसला नही किया अंजाम भुगनते को तैयार रेहना। नगर कोतवाली पहुचे पॉलटेक्नीक के छात्र शुभम वर्मा, शशांक वार्ष्णेय, रवि शर्मा, यषवंत चौहान को जोकि कालेज के ही बरावर में बने हॉस्टल में रहते हे कल रात एक कार में सवार कुछ अज्ञात युवक उनके हॉस्टल पहुंचे और कहा की तुम्हारे शिकायत करने से तुम्हारे टिचर दीनदयाल काफी परेषान हे अगर तुमने अपनी शिकायत वापस नही ली और उन्हे कुछ हो गया तो अपना अंजाम भुतने को तैयार रहना। हम बतां दें की अभी चार दिन पुर्व अपने टिचर दीनदयाल के खिलाफ छात्र-छात्राओं द्वारा अश्लील बाते एंव जातिवादी सूचक षब्दो को प्रयोग और जानबूझकर कापीयो में

पॉलटेक्नीक अज्ञात युवको युवको द्वारा मिली धमकी की तहरीर देते हुये छात्र।

मार्क कम देने का भी कथित आरेप लगाया इसी को से उग्र होकर छात्रो द्वारा सड़क जाम एंव कालेज परिसर में आरोपी टिचर को तत्काल हटाने की मांग पर अड़ गये दसी सन्दर्भ में प्रधानाचार्य वी.डी. षर्मा ने टीचर के खिलाफएक चार सदस्यो की जांच कमेंटी बनाई और अपनी रिर्पोट सात दिन में सौपने को कहा मगर अभी चार दिन ही हुये थे की पिड़ित बच्चो को अज्ञात युवको द्वारा जान डरा-धमकाने की शिकायत मिलने लगी।

कोतवाली प्रभारी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुये बताया की कालेज के छात्रो द्वारा डरा धमकाने की तहरीर मील गई जांच की जा रही जल्द ही आरेपीयो को धर पकड़ लिया जायेंगा।

राशन डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओ ने खोला मोर्चा

दीपांशु शर्मा

जहांगीराबाद-नगर जहांगीरबाद के पुख्ता बाजार स्थित मौहल्ला न्यू पाठक में मैसर्स हुकम सिंह के खिलाफ उपभोक्ताओ ने जमकर हंगामा काटा, उपभोक्ताओ का कहना था कि डीलर जितनी यूनिट होती हैं उससे कम यूनिट बाटंता हैं,वहीं पूर्व सभाषद रफीक मास्टर ने कहा कि डीलर की बार बार शिकायत के बावजूद कोई भी कार्यवाही प्रशासनिक स्तर पर नही होती, डीलर मात्र एक या दो दिन ही राशन बाटंता हैं प्रत्येक राशन पर एक या दो यूनिट राशन कम देता हैं और उन्होने जिला आपूर्ति कार्यालय से एक आरटीआई के तहत वितरण नियमावली व मैसर्स हुकंम सिंह के यहां चल रहे उपभाक्ताओ की लिस्ट मांगी थी लगभग दो माह हो चुके आज तक उन्हे आरटीआई का जबाब नही मिला हैं वहीं व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष इलियास मलिक ने कहा कि राशन डीलर का रवैया तानाशाही पूर्ण हैं शीघ्र ही उपभोक्ताओ को लेकर वह उपजिलाधिकारी से मिलेंगें, प्रदर्शन करने वालो में नफीस, शायरा,भूरी, बबली, समरजहां, सलमान,रहीमन, समीना, समेत आदि उपभोक्ता मौजूद रहें।

"डीलर की शिकायतें आ रही हैं शिकायतो की जावं कराकर डीलर के खिलाफ कडी से कडी कार्यवाही की जायेंगी," -सदानंद गुप्ता, उपजिलाधिकारी अनूपशहर

कम रेटो पर बिफरे किसान, किया जमकर हंगामा

किसानो को उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नही किया जायेंगा- एसडीएम

जहांगीराबाद। नगर की नवीन अनाज मंडी में धान काफी मात्रा में आ रहा हे जिससे धान की आवा गमन पर भारी दिक्कत हो रही इसी के चलते दो दिन मंडी को बंद कर दिया जिसके खुलने पर किसानो के धान किमत अचनक धड़ाम हो गई जिससे किसान उग्र हो गये और जमकर हंगामा किया। हम बतां दे की नगर की मंडी धान खरीदने में पूरे जनपद अपना प्रथम स्थान रखती जिसके चलते आसपास के जनपदो के भी किसान अपना धान बेचने के लिये यंहा आते हे मगर दो दिन मंडी में काफी मात्रा में धान आ गया जिसके चलते दो दिन के लिये मंडी को बदे कर दिया आज जब सुबहां मंडी खुली तो धान के रेटो में काफी गिरावट आई जिसके चलते किसान आक्रोशित हो गये और जमकर नारे बाजी करने लगे जिसकी

मंडी में धान की कम कीमत पर भड़के किसानो को समझाते अधिकारीगण।

को लेकर किसान एंव पल्लेदारो में आपास में झगड़ा एंव मारपीट षुरू हो गई जिसमें एक किसान भी घायल हो गया। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी धर्मवीर सिंह ने घायल किसान को सीएचसी के लिये रेफर कर उग्र किसानो को शान्त किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदांनद गुप्ता सीओ मनीश यदाव, अनूपशहर कोतवाली प्रभारी सत्य प्रकाश पटेल भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे और स्थित को काबू कर किसानो एंव व्यापारीयो को को समाझाते हुये दोबारे से धान की खरीद को शुरू कराया।

नगर में नपा अधिकारियो ने चलाया स्वच्छता अभियान

जहांगीराबाद- नगर जहांगीराबाद में नगरपालिका परिषद के अधिकारियो व कर्मचारियो द्धारा स्वच्छता अभियान चलाया गया,इस स्वच्छता अभियान में ई.ओ संदीप सक्सैना, प्रधान लिपिक संतोष भारद्धाज व नपा के सभी बडे छोटे कर्मचारियो ने हिस्सा लिया, इस मौके पर ई.ओ सन्दीप सक्सैना व प्रधान लिपिक संतोष भारद्धाज ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही है जो की नगर की सफाई के लिए आरम्भ की गयी है, इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल है।यह एक राजनीति मुक्त अभियान है और देशभक्ति से प्रेरित है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी है और इस देश को स्वच्छ देश बनाने के लिए हर भारतीय नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर पर लोगों ने पहल की है। शिक्षक और स्कूल के छात्र इसमें पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ शामिल हो रहे है और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहे है।इस मौके पर लेखाकार उधम सिंह,कम्प्यूटर आपॅरेटर राजकुमार, अशोक कुमार,डोरीलाल शर्मा, जगदीश सैनी, विवेक सैनी,आदि नपा के सफाइ कर्मचारी मौजूद रहें।

दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन रोक- चुनाव आयोग

नई दिल्ली चुनाव आयोग ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने आजीवन रोक लगने की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीमकोर्ट में कहा कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधयों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए। आयोग ने अपनी यह मांग सरकार के सामने भी रखी है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह इस सिलसिले में कानून संशोधित करने के लिए सरकार को भी लिख चुका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात का प्रुफ मांगते हुए कहा कि कब लिखा है सरकार को, दिखाओ।

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर

आजीवन रोक की मांग वाली चप्स् पर सुनवाई के दौरान दागी नेताओं के ख़लिाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी गयी थी। कोर्ट ने कहा था, क्या याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ब्यौरा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सजा होने के बाद 6 साल की रोक पर बहस कर रहे हो लेकिन जब कोर्ट में केस 20-20 साल लंबित रहता है और 4 टर्म बीत जाते है, इसके बाद छह साल की रोक का क्या मतलब है। कोर्ट ने कहा कि 20-20 साल केस लंबित रहते है जबकि कोर्ट का आदेश है कि ऐसे मामलों में 6 महीने से ज्यादा स्टे नही दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह बहस इसलिए है क्योंकि मुकदमों में जल्दी फैसला नहीं आता।

हरियाणा सरकार का तुगलकी फरमान, मास्टरजी बनेंगे पुजारी!

तिलक भारद्वाज

यमुनानगर हरियाणा में मुमकिन है कि अब सरकारी स्कूल के टीचर मंदिरों में पुजारी या प्रसाद बांटने वाले की भूमिका में नजर आएं। हालांकि टीचर इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार नजर नहीं आ रहे, लेकिन सरकार की मंशा कुछ ऐसी ही है। जिसको लेकर टीचर भड़क उठे हैं।

दरअसल यमुनानगर में हर साल लगने वाले मशहूर ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ती है। जिसमें सरकार टीचरों की ड्यूटी लगाना चाहती है। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देकर उनसे पुजारी और प्रसाद बंटवाने का काम करवाना चाहती है। ट्रेनिंग के लिए 29 अक्टूबर को टीचरों को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। लेकिन सरकार के इस कदम से नाराज टीचर ट्रेनिंग में हिस्सा

लेने पहुंचे ही नहीं। जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लेटर जारी कर एक बार फिर 30 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया गया और गैरहाजिर रहनेवाले टीचरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

सरकार के इस रुख से सरकारी टीचर उबल बड़े हैं। वो इसे ना सिर्फ तुगलकी फरमान करार दे रहे हैं बल्कि इसके खिलाफ जोर-शोर से आवाज बुलंद करने की धमकी भी दे रहे हैं। टीचर्स एसोसिएशन राज्य में लगातार शिक्षा के स्तर में गिरावट आने के पीछे टीचरों से दूसरे काम लिए जाने को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसके मुताबिक बच्चों की पढ़ाई को तवज्जो ना देकर सरकार का ध्यान टीचरों से जलती पराली की निगरानी कराने जैसे काम पर रहता है। इसके चलते बच्चों का सिलेबल पीछे छूट जाता है, जिसका असर रिजल्ट पर पड़ता है। हद तो ये है कि अब सरकार टीचरों से पुजारी और प्रसाद बंटवाने का काम भी कराना चाहती है। लेकिन टीचर इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे।

आंदोलन की चेतावनी देकर टीचरों ने सीधा-सीधा ये संदेश दे दिया है कि वो इस मुद्दे पर सरकार से आर-पार के मूड में हैं। जाहिर है अब इस पर सरकार के रुख का इंतजार रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हजारों डिग्रियां अमान्य, अब यूं बचा सकते हैं डिग्री

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों पर नियामक प्राधिकारों की पूर्व मंजूरी के बिना 2018-19 सत्र से कोई भी दूरस्थ पाठ्यक्रम चलाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए देश की चार डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2001-2005 सत्र के बाद से दूरस्थ शिक्षा के जरिए हजारों छात्रों को मिली इंजीनियरिंग की डिग्री रद्द कर दी है। कोर्ट ने ऐसे चार संस्थानों को पिछली तारीख से मंजूरी देने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज से पिछले 16 साल में पत्राचार से इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले हजारों छात्रों के सामने बड़ा सकंट खड़ा हो गया है।

क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही इन डिग्रियों के दम पर नौकरी हासिल करने वालों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्रभावित स्नातकों को अपनी डिग्री बचाने के लिए एआईसीटीई की परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा में सफल होने पर उनकी डिग्री बच सकती है। विश्वविद्यालयों को इन सभी छात्रों से वसूली गई फीस व अन्य खर्च लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को आगामी अकादमी सत्र से बिना संबंधित अथॉरिटी (यूजीसी, एआईसीटीई, डीइसी) से अनुमति के दूरस्थ शिक्षा के जरिए तकनीकी शिक्षा से जुड़े किसी भी कोर्स को चलाने पर रोक लगाने के बाद अब डीम्ड विश्वविद्यालयों को हर कोर्स के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने एक महीने के भीतर डीम्ड यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी शब्द हटाने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने डीम्ड यूनिवर्सिटियों को इंजीनियरिंग कोर्स चलाने की अनुमति देने में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीठ ने नामचीन लोगों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है।

अब घर-घर जाएंगे महाराष्ट्र के अस्पताल

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक अभियान के तहत चार नवबंर को राज्य के चौरिटेबल अस्पताल फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले लोगों और मुंबई की झुग्गी बस्तियों में गंदगी के बीच रहने वाले गरीब लोगों के घर-घर जाकर उनकी सेहत की जांच और उपचार करेंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि श्गरीब मरीजों के द्वार, चौरिटेबल अस्पतालश् नामक मुहिम को गरीब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। राज्य चौरिटी आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य चौरिटी आयुक्त शिवकुमार डीगे द्वारा शुरू मुहिम के तहत अस्पताल में उपचार की आवश्यकता वाले मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि यह मुहिम उन तमाम शिकायतों के संदर्भ में भी है जिनमें आरोप लगते रहे हैं कि ये अस्पताल उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गरीबों एवं वंचित तबके के मरीजों के लिये निर्धारित सभी 20 प्रतिशत बिस्तरों को उनके लिये आरक्षित नहीं करते।

संपर्क करने पर डीगे ने कहा कि अस्पतालों के साथ हुई उनकी पहली बैठक में सभी चौरिटेबल अस्पताल इस मुहिम को लागू करने के लिए तुरंत सहमत हो गए। मुहिम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अभी दो और बैठकें होंगी।

सदस्यता राशि निम्न बैंक में जमा कराकर सदस्यता ग्रहण की जा सकती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार
आईडीबीआई बैंक
खाता संख्या 1481020000007368
पंजाब नेशनल बैंक
खाता संख्या 3698002100029521
नोट-नगद सहयोग राशि स्वीकार नहीं की जाती है।

पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है

20 असफल देशों की लिस्ट में शामिल

नई दिल्ली आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके पाकिस्तान को एक बार फिर आइना दिखाया गया है। फ्रेजाइल स्टेट्स इंडेक्स 2017 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को 20 असफल देशों की फेहरिस्त में रखा गया है और उसे कई कड़ी नसीहतें दी गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को पड़ोसी देशों में आतंकी भेजकर वहां अस्थिरता फैलाने की जगह खुद को बर्बादी से बचाने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता करनी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को पड़ोसी देशों, जैसे भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ धीमा युद्ध छेड़ने या आतंकवाद फैलाने की जगह विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान ने इस मकसद से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), हरकत-उल-मुजाहिदीन (एचयूएम), सिपह-ए-साहब पाकिस्तान (एसएसपी), अहले सुन्नत वल जमात (एएसडब्ल्यूजे), लश्कर-ए-झांगवी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकी संगठन खड़े किए।

अब पाकिस्तान को दुनिया के शीर्ष 20 फ्रेजाइल स्टेट्स में शामिल होने के बाद यह समझना होगा कि जिस आतंकवाद को वह अपने पड़ोसी देश भारत को परेशान करने के उद्देश्य से इस्तेमाल करता रहा है, वह खुद उसके लिए नासूर बन चुका है। यह इंडेक्स इसी ओर इशारा करता है।

सावधान! 'आटा' आपको कर सकता है बीमार, ...बहुत बीमार

बाबू अंसारी

स्योहारा, बिजनौर। वैसे तो आज के इस युग में मिलावट खोरी हर चीज में होने लगी है, खाने पीने की चीजों से लेकर,बीमार इंसान के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ तक भी बाजार में नकली बिक रही है, वही घर बनाने में लगने वाली ईंट, सीमेंट, सरया,रेत बजरी,में भी मिलावट आम हो गई है।

गेंहू से आटा, आटे से रोटी, रोटी से फिर आटा?

घर की चार दिवारी से निकल कर आगे बढ़े तो खेल खलिहान में उगने वाली फसलों में खाद और कीटनाशक दवाओ में मिलावट, सब्जियों में मिलावट,दाल चावलों व तेलों में मिलावट किसी से छुपी हुई नही है, परिवहन क्षेत्र में आये तो वाहनों में डलने वाले मोबिल आयल व डीजल पेट्रोल में मिलावट के बारे में जनता के साथ साथ मिलावट खोरों की धड़ पकड़ के लिए बनाये गए महकमें को भी बा खूबी मालुम है या यु कहे की उसी महकमें की छत्र छाया में मिलावट खोरी का धंदा दिन दुनी-रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, जैसे-जैसे ये धंदा तरक्की कर रहा है वैसे-वैसे ही महकमें में कार्यरत सरकारी कर्मियो की भी इमारतें बुलन्द हो रही है।

आइये अब आपको खबर के पहलू पर ले चलते है. (गेंहू से आटा आटे से रोटी,रोटी से फिर आटा) जी हाँ ये बात आपको बात आपको अजीब सी लगेंगी पर सूत्रो की माने तो हमारे और आपके घरों में जो बासी रोटी बच जाती थी जिन्हें घर की महिलाये सुखा लेती थी और किसी गाय भेंस पालने वाले को मुफ्त या कुछ पैसे लेकर दे देती थी मिलावट खोरों की मेहरबानी से आज वो रोटी 8, से 10, रूपये किलो बिक रही है, कही महिलाये तो कही पुरुष घर-घर जाकर सुखी रोटियाँ की खरीदारी कर रहे है। और नगर व गाँवों में लगी छोटी आटा मिलों में जाकर बैच रहे है।

जहां पर सुखी रोटियों को एक बार फिर चक्की में पीस कर इन रोटियों का आटा बनाया जा रहा है, और 5, व 10, किलो के थैलो में भरकर दुकानों पर बेचा जा रहा है जहां से ये आपके और हमारे घरों की रसोई तक पहुच रहा है। पर अनगिनत चीजों में होती मिलावट खोरी से खबरदार होते हुए भी अनजान बना हुआ सम्बंधित विभाग रोटी से आटा बनाने वाले धंदे की और से भी आँख मूंदे हुए है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक, अखिल''कृपाशंकर'' ने इण्डियन प्रेस, राजेंद्र नगर, मेरठ से छपवाकर सी-92, श्रद्धापुरी-प्रथम, कंकरखेड़ा, मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रकाशितकिया।मो0-09412421700,09045001009वेबसाइट-www.rashtriyamanavadhikar.com, Email-rashtriyamanavadhikar@gmail.com